ब्रिटेन वोट्स फॉर ब्रेक्जिट

लेखक-करण थापर (टेलीविजन एंकर)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

14 दिसम्बर, 2019

"अपनी जीत के साथ, बोरिस जॉनसन के पास यह मौका है कि वह अपनी योजनाओं के अनुसार यू.के. को एक नया रूप प्रदान करे।"

ब्रिटिश चुनाव परिणाम राजनीतिक है लेकिन यह किसी भूकंप से कम नहीं था। इस बात की अब संभावना बढ़ गयी है कि आने वाले महीनों में यूनाइटेड किंगडम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और संभवत: क्षेत्रीय रूप से भी एक बहुत अलग देश बन जाएगा। लगभग एक दशक के कमजोर या बहुदलीय प्रधानमंत्रियों के बाद, बोरिस जॉनसन की सरकार शक्तिशाली प्रतीत हो रही है।

ब्रिटिश संसद के 650 सदस्यीय निम्न सदन 'हाउस आफ कॉमन्स' में कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत से 78 सीटें अधिक है। इस चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी को केवल 203 सीटें मिली है, जो 1935 के बाद लेबर पार्टी की सबसे करारी हार है।

इस चुनाव के बाद सबसे बड़ा बदलाव ब्रेक्जिट होगा। ब्रिटेन 31 जनवरी, 2020 को यूरोप से अलग हो जाएगा। श्री जॉनसन के पास न केवल यूरोपीय संघ के साथ, बल्कि ब्रिटेन के अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के साथ एक व्यापार सौदा सुरक्षित करने के लिए 11 महीने हैं। सवाल यह है कि इसे इतने कम समय में किया जा सकता है या नहीं? यह हालाँकि यह आसान नहीं होगा और यदि ये इसमें विफल रहते है तो संक्रमण की अवधि ब्रेक्जिट के साथ समाप्त हो जाएगी जिससे हर कोई बचना चाहता है।

वर्किंग क्लास वोट

जॉनसन की जीत से राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में कई बदलाव आएंगे। 1987 में मार्गरेट थैचर की जीत के बाद से 364 सीटों और 45% वोट के साथ उनके रूढ़िवादियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल किया है। वास्तव में, वोट शेयर के लिहाज से यह 1970 के बाद से सबसे अच्छा परिणाम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें लेबर पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले मिडलैंड्स, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में भी बड़ा फायदा हुआ है। टोनी ब्लेयर की सेजफील्ड कब्जे में आ गयी, साथ ही स्टोक-ऑन-ट्रेंट और ग्रेट ग्रिम्बी, जो कभी टोरीज से नहीं जीते गए थे, अब उनके कब्जे में हैं।

विदित हो कि 1935 के बाद यह पार्टी की सबसे बुरी हार है। 1983 में माइकल फुट द्वारा दी गई 209 सीटें के मुकाबले 203 सीटें कम हैं। उस समय पार्टी का घोषणा पत्र 'इतिहास का सबसे लंबा सुसाइड नोट' करार दिया गया था।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्री कॉर्बिन ने घोषणा की है कि वह अगले चुनावों में लेबर पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे। सच्चाई यह है कि लेबर पार्टी को न केवल ब्रेक्जिट ने हराया है, बल्कि उनकी हार इसलिए भी हुई है क्योंकि ब्रिटेन श्री कॉर्बिन की समाजवादी नीतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह इस पराजय के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते है।

स्टर्जन कारक

यह लिबरल डेमोक्रेट के नेता के लिए एक निराशाजनक चुनाव रहा है, जिसके नेता 'जो स्विन्सन' इस चुनाव में अपनी सीट हार गए है। पार्टी में सिर्फ 11 सांसदों ने सफलता पायी। लेकिन स्कॉटलैंड में सीमा पार यह निकोला स्टर्जन के स्कॉटिश राष्ट्रवादियों

के लिए एक शानदार परिणाम था। 59 सीटों में से उनकी पार्टी को 48 सीटें मिलीं, जिससे उसकी संख्या 13 हो गई और 45% वोट शेयर हासिल किया। बोरिस जॉनसन के साथ वह इस चुनाव के दूसरे चौंपियन है।

संदेह के बिना स्कॉटिश राष्ट्रवादी स्कॉटलैंड के लिए स्वतंत्रता पर एक बार फिर से जनमत संग्रह की मांग करेंगे। उनका मानना है कि उनके पास इसके लिए जनादेश है। दूसरी ओर, मिस्टर जॉनसन पहले ही कह चुके हैं कि इसके लिए सहमत नहीं है। दोनों राजनेताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट और अपरिहार्य टकराव होना अब लाजमी है।

इन परिस्थितियों में, श्री जॉनसन एक प्रधानमंत्री के रूप में क्या फैसला लेंगे वह देखने वाला होगा। श्री जॉनसन अपनी पार्टी के निर्विवाद नेता हैं, जो संसद में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। वह वस्तुतः वही कर सकते है जो वे चाहते है। उनके पास अब एक अवसर है जहाँ वे अपनी मान्यताओं के अनुसार यू.के. को फिर से एक नया रूप प्रदान कर सकते है। राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में, उन्होंने अपने विजय भाषण में कंजर्वेटिव पार्टी को 'एक राष्ट्र पार्टी' के रूप में परिभाषित किया।

लेबर के लिए आगे क्या?

बहुत कुछ लेबर के साथ भी हो सकता है। यदि पार्टी को करारी हार से उबरना है तो श्री कॉर्बिन को इसका नेतृत्व करना चाहिए और अपनी गलतियों से सिख ले कर उस पर काम करना चाहिए, जैसा कि 1997 में टोनी ब्लेयर ने की थी और इससे पार्टी को लगातार तीन चुनाव में जीत मिली थी। हांलाकि, कॉर्बिन के इस्तीफा देने के बाद बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन लैबर के नए नेता के रूप में उभरता है।

2016 में ब्रेक्जिट आंदोलन के नेता के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे संरक्षणवाद, वैश्विकतावाद और यहां तक कि कई ब्रेक्जिटर्स के आव्रजन विरोधी स्टैंड को साझा नहीं करेंगे। अब, प्रधानमंत्री के रूप में, वह ब्रेक्जिट के कराण सिंगापुर-ऑन-थेम्स विजन को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मार्च में अपने पहले बजट भाषण में कट्टरपंथी कर सुधार शुरू करने, विनियमन को कम करने और उद्यम के लिए प्रोत्साहन को बढ़ावा देने की संभावना है।

हालाँकि, कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपायों को लागू करने की संभावना बढ़ गयी है। जॉनसन के विजयी भाषण ने उन्हें सार्वजनिक खर्च बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया है विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य पर। इससे नेशनल हेल्थ सर्विस एक महत्वपूर्ण लाभार्थी होगा।

विदेश नीति के संदर्भ में, श्री जॉनसन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएंगे, जो वैसे भी उन्हें एक मित्र के रूप में मानते हैं। लेकिन वह यूरोप के साथ प्रभावी संबंध बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में समान रूप से जागरूक रहेगा। उन्होंने बार-बार कहा है कि वह यूरोपीय विरोधी नहीं हैं। लिटिल इंग्लैंड या ब्रिटिश अलगाववाद उनकी सोच का हिस्सा नहीं है।

भारत के लिए

हम श्री जॉनसन से एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में भारत के लिए स्नेह की उम्मीद कर सकते हैं। हालाँकि, श्री जॉनसन अपनी पत्नी मरीना, जो अर्ध-भारतीय है, से अलग हो गये है, लेकिन इनके चार बच्चों में भारतीय रक्त ही बह रहा है। वह भारत में लगातार आने वाले आगंतुकों में से एक है, जिसमें पिछले साल रणथंभौर की एक अप्रकाशित यात्रा भी शामिल है।

एकमात्र चिंता श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से है, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नागरिकता संशोधन अधिनियम और हिंदुत्व पर व्यापक तनाव शामिल है। वह सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकते है लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अस्वीकृति व्यक्त कर सकते है।

विडंबना यह है कि यूरोप से ब्रिटेन की दूरी होने के बावजूद, दुनिया यह देखने के लिए उत्सुक है कि यह कितना और किस दिशा में बदलने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1945 और 1979 के चुनाव परिवर्तनकारी रहे है और इस बार का चुनाव भी इसी श्रेणी से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसकी भी संभावना है कि मिस्टर जॉनसन, जिन्हें गैर-गंभीर राजनीतिज्ञ माना जाता है, अब इनकी तुलना क्लेमेंट एटली और मार्गरेट थैचर से की जाने लगे।

ब्रेक्जिट

- यह मुख्यत: दो शब्दों ब्रिटेन (Britain) आरै एग्जिट (Exit) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ब्रिटेन का यूरोपीय संघ (European Union-EU) से बाहर निकलना है।
- ब्रिटेन की जनता ने ब्रिटेन की पहचान, आजादी और संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से बाहर जाने का फैसला लिया।
- यूरोपीय संघ (निकासी) विधेयक के कानून बन जाने के उपरांत इसने 2017 के यूरोपीय समुदाय अधिनियम का स्थान ले लिया है।
- यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के समझौते के लिये तैयार मसौदे को ब्रेक्जिट ड्राफ्ट डील कहा जा रहा है

बाहर निकलने की मांग क्यों?

1. सदस्यता शुल्क

- ईयू हर साल सदस्यता शुल्क के तौर पर ब्रिटेन से बिलियन ऑफ पाउंड लेता है तथा बदले में उसे बहुत कम राशि मिलती है।
- यह राशि लगभग 13 बिलियन पाउंड है, जो दूसरे देशों की अपेक्षा काफी अधिक है।
- सदस्यता के लिये ईयू के सभी 28 देश कुछ न कुछ राशि EU को देते हैं, लेकिन ब्रिटेन के लिये यह राशि काफी अधिक है और बदले में उसे सिर्फ 7 बिलियन यूरो वापस मिलते हैं। अत: UK (ब्रिटेन) को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

2. प्रशासनिक अड़चन

- UK में कोई भी प्रशासनिक कार्य करने के दौरान काफी अड़चनें आती हैं। बहुत अधिक डॉक्यूमेंटेशन तथा बहुत सारे कार्यालयों द्वारा काम होता है। कई सारी प्रणालियाँ हैं, जिनको पूरा करना पड़ता है।
- तमाम ऐसे प्रतिबंध हैं, जिनसे UK के विकास में रुकावट आ रही है तथा यूरोपीय यूनियन UK को पीछे ढकेल रही है, उसे आगे बढ़ने से रोक रही है।

3. स्वायत्तता

- लोगों का कहना है कि ईयू इंग्लैंड को उसके अधिकारों और स्वयं कानून बनाने से वंचित कर रहा है। खासतौर से फिशरीज से संबंधित कानून।
- UK के चारों ओर फिशरीज इंडस्ट्री काफी विकसित है और इस उद्योग को लेकर नियम-विनियम ईयू के द्वारा बनाए जाते हैं।
- ईयू की संसद तय करती है कि UK के मछुआरे कितनी मात्रा में मछली पकड़ सकते हैं तथा एक्सपोर्ट रेट क्या रहेगा।

4. अर्थव्यवस्था

- अगर यूरोपीय यूनियन से न्न अलग हो जाता है, तो वह अपने आपको फाइनेंसियल सुपर पॉवर बना सकता है क्योंकि लंदन को पहले से ही वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वहाँ का वित्तीय बाजार दुनिया के बड़े बाजारों में से एक है।
- जबकि ईयू द्वारा UK को ऐसा करने से रोका जा रहा है।

5. इमीग्रेशन

- यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि सीरिया में सिविल वार के चलते काफी संख्या में अप्रवासी भागकर यूरोप आ रहे हैं।
- इमीग्रेशन नीति भी ईयू तय करता है, न कि UK, अगर वह ईयू से हट जाता है तो उसे अपनी खुद की इमीग्रेशन नीति तय करने का अधिकार होगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. ब्रेक्जिट का संबंध ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से है।
2. यूरोपीय संघ में शामिल देशों के लिए आप्रवास नीति यूरोपीय संघ द्वारा बनाया जाता है।
3. यूरोपीय संघ में कुल 29 देश है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलने वाला तीसरा देश होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements:-**

1. Brexit related to Britain's exit from the European Union.
2. The immigration policy made by the European Union for the countries involved in the European Union.
3. There are a total of 29 countries in the European Union. Britain will be the third country to exit form the European Union.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) 1 and 2

(c) 2 and 3 (d) All of the above

नोट : 13 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: ब्रिटेन में हालिया चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी की ऐतिहासिक जीत ब्रिटेन के लिए राजनैतिक और भौगोलिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? भारत के संदर्भ में ब्रिटेन से संबंधों पर पड़ने वाले असर को भी साथ में दर्शाए। (250 शब्द)

The historic victory of the Conservative Party in the recent elections in Britain will prove to be extremely important politically and geographically for Britain. Do you agree with this statement? In the context of India, also show the impact on relations with Britain. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।